एनपीएस में बड़ा सुधार, रिटायरमेंट की प्लानिंग हुई आसान

जब सुविधा पड़ने लगे 'जान' पर भारी

प्रकाशन का गौरवशाली 15वाँ वर्ष

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 32 | मूल्य 05 रुपये | 28 दिसंबर, 2025 - 03 जनवरी, 2026

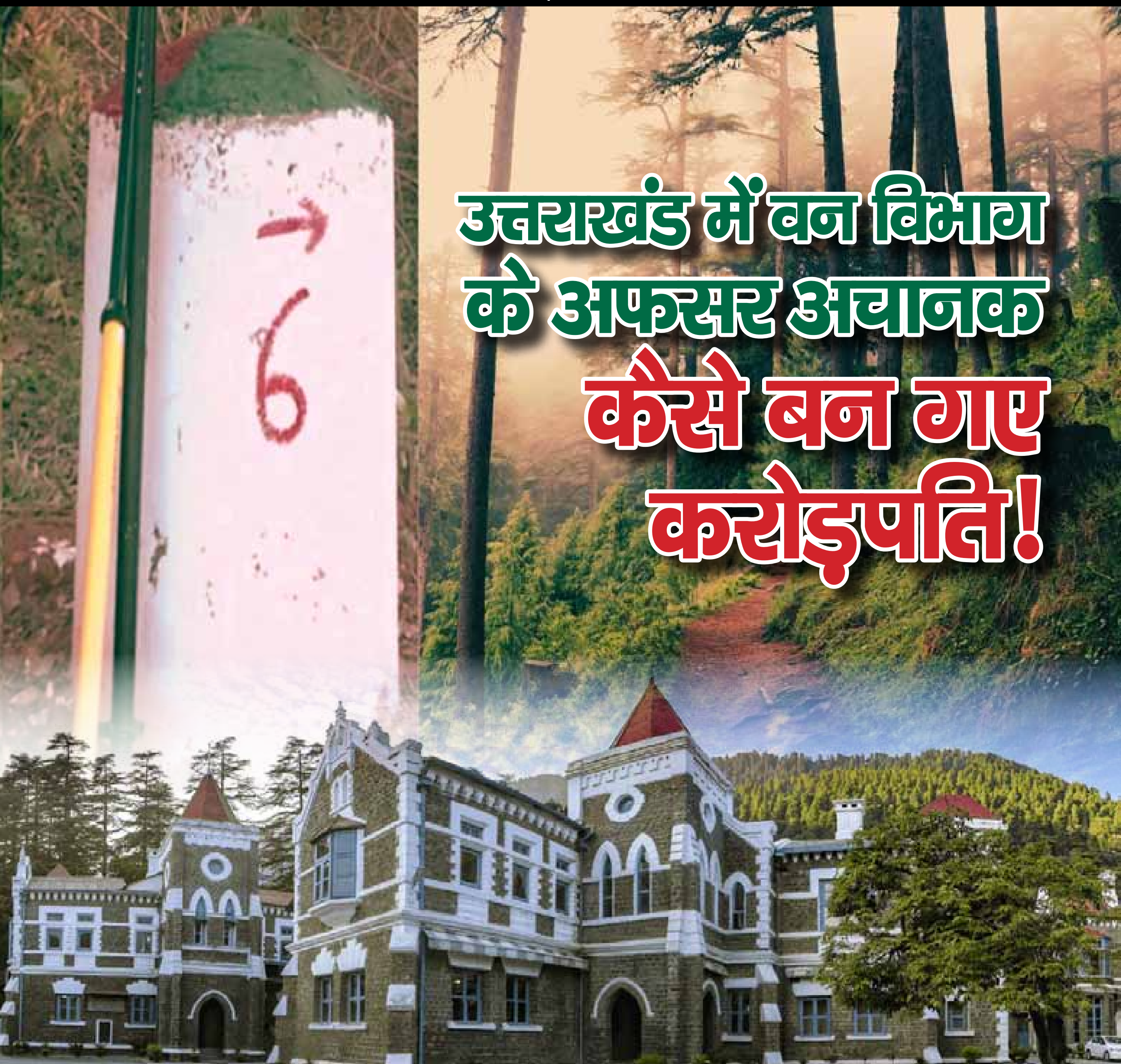

उत्तराखंड में वन विभाग के अफसर अचानक कैसे बन गए करोड़पति!

युग पुरूष, उत्तराखण्ड के प्रणेता, जनप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री

"भारत रत्न"

स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी

की जयंती पर

समस्त उत्तराखण्ड वासियों की ओर से शत्-शत् नमन

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR

वर्ष 15 | अंक 32

दिव्य हिमगिरि

28 दिसंबर, 2025 - 03 जनवरी, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

क्रिसमिस के दिन यह कैसा शोर!

दुनिया भर में भारत को विविधताओं से भरी सांस्कृतिक छवियों वाले एक ऐसे देश के रूप में देखा-जाना जाता है, जहां अलग-अलग धर्मों के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते और एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते आए हैं। मगर हाल के वर्षों में कुछ खास त्योहारों के ठीक पहले जिस तरह द्वेष का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाने लगी है, वह न केवल देश में सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, बल्कि मानवीय तकाजों के भी विरुद्ध है। क्रिसमस को ईसाई धर्म से जुड़े लोगों का त्योहार माना जाता है, लेकिन इसमें आमतौर पर देश में सभी धर्मों के लोग उत्साह के साथ शामिल होते रहे हैं। विडंबना यह है कि अब कुछ असामाजिक तत्त्व क्रिसमस के मौके पर देश के ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाने लगे हैं और इसका सीधा नुकसान देश की छवि को हो रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष फिर क्रिसमस के मौके पर छत्तीसगढ़ और असम सहित कुछ राज्यों में ईसाई समुदाय के प्रार्थना स्थलों और अन्य जगहों पर दक्षिणपंथी समूहों ने हमला किया और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ मचाई। सवाल है कि वे कौन लोग हैं, जो सद्भाव के माहौल में नफरत घोलना चाहते हैं और उन्हें देश के अल्पसंख्यक या अन्य समुदायों के पर्व-त्योहार से परेशानी होने लगी है। क्या मानवीयता के मूल्यों को अपनी आस्था का सबसे अहम पक्ष मानने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य समुदाय के त्योहार से इस कदर दुश्मनी रख सकता है? सद्भाव या सौहार्द के साथ किसी धार्मिक उत्सव को मनाए जाने से किसे दिक्कत हो सकती है? केवल निराधार आरोपों का हवाला देकर किसी ऐसे त्योहार पर अराजकता फैलाने का क्या मकसद हो सकता है, जिसमें देश के सभी धर्मों के लोग या तो सहज रहते हैं या फिर उसमें शामिल होते हैं? कथित धर्म परिवर्तन के आरोप अगर लगाए भी जाते हैं, तो इस मसले पर सरकार और प्रशासन अपना काम करेंगे या कुछ अराजक और असामाजिक तत्त्वों को अपनी ओर से हिंसा करने की छूट मिल जाती है? किसी समुदाय के भीतर डर पैदा करके किस तरह से धर्म की सेवा की जा सकती है? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी बहाने से अन्य धार्मिक समूहों के खिलाफ हिंसा करना या तोड़फोड़ मचाना वास्तव में अपने ही देश की सांस्कृतिक छवि को नकारात्मक बनाना है। अगर इस तरह की प्रवृत्तियों को तुरंत नहीं रोका गया, तो इससे आपसी सद्भाव का माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा होगी। इतना तय है कि देश के संविधान का सम्मान करने वाली सरकारें और ज्यादातर संवेदनशील लोग धर्म के नाम पर टकराव तथा तनाव पैदा करने की कोशिशों का समर्थन नहीं करते। यही वजह है कि कई जगहों पर क्रिसमस पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि किसी भी पर्व-त्योहार के मौके पर सांप्रदायिकता फैलाने वाले तत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। विचित्र यह भी है कि क्रिसमस के मौके पर एक ओर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईसाई समुदाय के साथ मेलजोल, शांति और सद्भाव का संदेश दे रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्त्व तोड़फोड़ और अराजकता फैलाने में लगे थे। देश में सभी धर्मों के पर्व-त्योहारों के अवसर पर सौहार्द तथा सद्भाव की जो परंपरा रही है, उसे बचाने और मजबूत करने के लिए सरकार और समाज को एक बार फिर ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

उत्तराखंड में वन विभाग के अफसर अचानक कैसे बन गए करोड़पति!

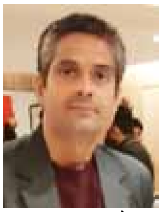

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड में वन संपदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के कंधों पर है, उन्हीं की अचानक बढ़ी दौलत को लेकर न्यायपालिका को भी हैरान कर दिया। राज्य में वन विभाग में कथित भ्रष्टाचार और वन भूमि से जुड़े गंभीर आरोप अब न्यायपालिका के सख्त रुख के दायरे में आ गए हैं। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कम समय में असामान्य रूप से संपत्ति अर्जित किए जाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला केवल व्यक्तिगत संपत्ति का नहीं, बल्कि राज्य की वन संपदा के संरक्षण से सीधे जुड़ा हुआ है। अदालत के समक्ष यह तथ्य सामने आया है कि प्रदेश में 7,375 वन सीमा स्तंभों के गायब होने से वन भूमि की वास्तविक सीमाएं ही संदिग्ध हो गई हैं। यह मामला केवल व्यक्तिगत संपत्ति तक सीमित नहीं, बल्कि राज्य की वन भूमि, प्रशासनिक ईमानदारी और सार्वजनिक विश्वास से सीधे जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली, अवैध कब्जों, वन सीमा स्तंभों के गायब होने और संभावित भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए याचिका में सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली, संभावित भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों को लेकर प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

उत्तराखंड में वन विभाग की कार्यप्रणाली और कथित भ्रष्टाचार एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। जिन अधिकारियों पर जंगलों की सुरक्षा, वन भूमि के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उन्हीं की अचानक बढ़ी संपत्ति और वन भूमि से जुड़े मामलों ने न्यायपालिका को चिंतित कर दिया है। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग के अफसरों द्व ारा कम समय में असामान्य रूप से संपत्ति अर्जित किए जाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे सामान्य प्रक्रिया से परे बताया है। अदालत ने साफ कहा है कि सीमित वेतन और तय सेवा शर्तों के बावजूद अधिकारियों का करोड़पति बन जाना गहन जांच की मांग करता है।यह याचिका पर्यावरण एक्टिविस्ट नरेश चौधरी ने दायर की थी। उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया से मसूरी फारेस्ट डिवीजन की सभी वन सीमाओं का वैज्ञानिक और जियो-रेफरेंस्ड सर्वे कराने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राज्य में राजस्व अधिकारियों के पास मौजूद या उनके नियंत्रण वाले सभी वन भूमि को एक निश्चित समय सीमा के भीतर वन विभाग को सौंप दिया जाए। वन सीमाओं को बहाल न करने से व्यावसायिक शोषण को बढ़ावा मिला है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष हुई। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला

केवल व्यक्तिगत संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव राज्य की वन संपदा, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनता के विश्वास से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि समय रहते इन मामलों पर कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो उत्तराखंड की बहुमूल्य वन भूमि को भारी नुकसान हो सकता है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष यह तथ्य भी रखा गया कि राज्य के विभिन्न वन क्षेत्रों में 7,375 वन सीमा स्तंभ (बाउंड्री पिलर) गायब पाए गए हैं। अदालत ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए कहा कि सीमा स्तंभों का इस तरह लापता होना किसी एक-दो घटनाओं का परिणाम नहीं हो सकता। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीमा स्तंभों का हटना या गायब होना वन भूमि पर अवैध कब्जे और गैरकानूनी निर्माण का रास्ता खोलता है, जिससे जंगलों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। याचिका में आरोप लगाया गया कि वन सीमा स्तंभों के गायब होने से वन भूमि को निजी भूमि के रूप में दर्शाकर उस पर होटल, रिसॉर्ट और अन्य व्यावसायिक निर्माण किए गए। अदालत को बताया गया कि कई मामलों में यह सब कुछ विभागीय मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यदि आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाते हैं, तो यह पूरे वन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की मांग को भी रिकॉर्ड पर लिया है। अदालत ने संकेत दिए कि यदि राज्य स्तर की जांच संतोषजनक नहीं पाई जाती, तो स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच कराए जाने पर विचार किया जा सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है। हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने जानना चाहा है कि वन सीमा स्तंभों के रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी किस विभाग की थी, उन्हें कब और किन परिस्थितियों में स्थापित किया गया था और उनके गायब होने के बाद क्या कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अधिकारियों की संपत्ति के स्रोतों और उनके सेवा रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सीमा स्तंभ प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन या अन्य कारणों से नष्ट हुए हैं, तो उसका विधिवत रिकॉर्ड और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी। बिना किसी ठोस दस्तावेज के यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि वन भूमि से जुड़े मामलों में लापरवाही को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में वन केवल पर्यावरण ही नहीं, बल्कि जीवन, जल और आजीविका का आधार हैं। यदि वन विभाग के भीतर ही भ्रष्टाचार पनपता है, तो इसका सीधा असर

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा-जंगलों में आग को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए

उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने राज्य में वनाग्नि की स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे पर्यावरण, जनजीवन और वन संपदा के लिए बड़ा खतरा बताया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हर साल गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के इंतजाम जमीन पर नजर नहीं आते। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जंगलों में आग को रोकने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का कितना पालन किया गया है। अदालत ने इस पूरे मामले में राज्य में वनाग्नि पर विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि केवल आंकड़े पेश करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी बताना होगा कि आग की घटनाओं को कम करने के लिए विभागीय स्तर पर क्या रणनीति अपनाई गई है। हाईकोर्ट ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक और फॉरेस्ट फोर्स को विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि वे जंगलों में आग की रोकथाम, त्वरित नियंत्रण और नुकसान के आकलन को लेकर स्पष्ट कार्ययोजना अदालत के समक्ष रखें। कोर्ट ने कहा कि वनाग्नि केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि कई बार मानवीय लापरवाही और जानबूझकर की गई गतिविधियों का परिणाम भी होती है, ऐसे में जिम्मेदारी तय करना बेहद जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जंगल केवल हरियाली का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि जल स्रोतों, जैव विविधता और ग्रामीण आजीविका का आधार हैं। जंगलों में आग लगने से न केवल हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है, बल्कि वन्यजीवों, ग्रामीण आबादी और पर्यावरण संतुलन पर भी गहरा असर पड़ता है। इसके बावजूद यदि हर वर्ष हालात एक जैसे बने रहें, तो यह प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने पूर्व में वनाग्नि को लेकर जारी किए गए निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि कागजों में बनी योजनाएं तब तक सार्थक नहीं हैं, जब तक उनका प्रभावी क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर न हो। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि आग लगने की घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया के लिए फॉरेस्ट फोर्स कितनी तैयार है और क्या आवश्यक संसाधन, उपकरण और मानव बल उपलब्ध कराए गए हैं। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कई मामलों में समय पर सूचना न मिलने और समन्वय की कमी के कारण आग बेकाबू हो जाती है। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि तकनीक के इस दौर में ऐसी लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने निर्देश दिए कि निगरानी व्यवस्था, फायर अलर्ट सिस्टम और स्थानीय स्तर पर सहभागिता को मजबूत किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वनाग्नि से हुए नुकसान का आंकलन कर उसके आधार पर भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जिम्मेदारी तय की जाए। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब निगाहें सरकार और वन विभाग की रिपोर्ट पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि अदालत के इस रुख के बाद उत्तराखंड में जंगलों में आग की समस्या से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है।

आम जनता और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। अदालत ने कहा कि शासन और प्रशासन का दायित्व है कि वे वन संपदा की रक्षा के लिए कठोर और पारदर्शी कदम उठाएं। मामले में यह पहलू भी सामने आया कि जिन क्षेत्रों में वन सीमा स्तंभ गायब हुए हैं, वहां अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कई स्थानों पर वन भूमि पर निर्माण कार्यों को नजरअंदाज किया गया या जानबूझकर अनदेखा किया गया। हाईकोर्ट ने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि इससे यह संकेत मिलता है कि नियमों का पालन कागजों तक सीमित रह गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वन विभाग का दायित्व केवल फाइलों में रिपोर्ट तैयार करना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जब विभाग के अधिकारी ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं, तो पूरे तंत्र की विश्वसनीयता पर आंच आती है। इसी कारण अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ की सख्त टिप्पणियां इस बात का संकेत हैं कि अदालत इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। यदि जांच आगे बढ़ती है, तो यह उत्तराखंड के वन विभाग में लंबे समय से लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की परतें खोल सकती है। कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य के प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार, वन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां अदालत के समक्ष क्या जवाब दाखिल करती हैं और क्या सीबीआई जांच की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाता है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि नैनीताल हाईकोर्ट के कड़े तेवर ने उत्तराखंड में वन विभाग से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

एनपीएस में बड़ा सुधार रिटायरमेंट की प्लानिंग हुई आसान

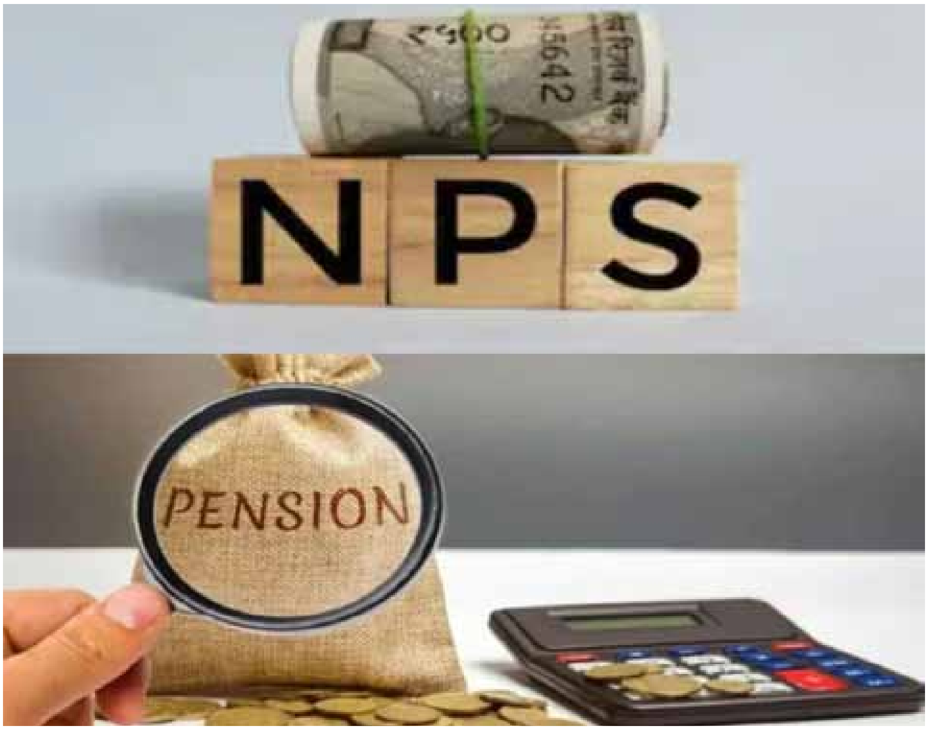

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेश करने वालों के लिए वर्ष 2025 एक निर्णायक साल बनकर सामने आया है। केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने रिटायरमेंट व्यवस्था को मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एनपीएस में व्यापक सुधार किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य न केवल निवेशकों को बेहतर रिटर्न और अधिक सुरक्षा देना है, बल्कि रिटायरमेंट प्लानिंग को ज्यादा लचीला और सरल बनाना भी है। सरकार की इस पहल के तहत एनपीएस से जुड़े निवेश विकल्पों का दायरा बढ़ाया गया है, निकासी के नियमों को आसान किया गया है और अलग-अलग वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियमों में व्यवहारिक बदलाव किए गए हैं। वर्ष 2025 में एनपीएस में कुल 10 बड़े बदलाव लागू किए गए हैं, जिनसे यह पेंशन योजना अब पहले से कहीं अधिक आकर्षक और उपयोगी बन गई है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

रिटायरमेंट का नाम आते ही आम आदमी के मन में सबसे पहले सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भर जीवन की चिंता उभरती है। नौकरी या व्यवसाय के सक्रिय वर्षों के बाद जब नियमित आमदनी रुक जाती है, तब पेंशन और बचत ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनती है। इसी भावनात्मक और आर्थिक जरूरत को समझते हुए सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को लगातार मजबूत किया है। वर्ष 2025 इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जब केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एनपीएस में 10 बड़े सुधार लागू कर इसे ज्यादा सुरक्षित, लचीला और आम आदमी के अनुकूल बना दिया। सबसे बड़ा बदलाव निवेश विकल्पों के विस्तार के रूप में सामने आया है। अब एनपीएस निवेशकों को इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट और संतुलित विकल्प मिल रहे हैं, जिससे वे अपनी उम्र और जोखिम क्षमता के अनुसार बेहतर निर्णय ले सकें। इसके साथ ही फंड आवंटन की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है, ताकि निवेशक बिना

जटिलता के अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकें। दूसरा अहम सुधार निकासी से जुड़े नियमों में किया गया है। अब आंशिक निकासी को ज्यादा आसान और व्यावहारिक बना दिया गया है। शिक्षा, इलाज, घर निर्माण या अन्य जरूरी परिस्थितियों में एनपीएस खाताधारक को अपने ही धन तक पहुंचने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। यह बदलाव एनपीएस को जीवन की वास्तविक जरूरतों से जोड़ता है। तीसरा बड़ा बदलाव कर लाभों से जुड़ा है। सरकार ने एनपीएस में निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट को और स्पष्ट किया है, जिससे नौकरीपेशा लोगों के साथ-साथ स्वरोजगार करने वाले भी बिना भ्रम के इस योजना का लाभ उठा सकें। इससे नियमित बचत और दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा मिला है। चौथा महत्वपूर्ण सुधार पेंशन यानी एन्युटी विकल्पों में किया गया है। 2025 में निवेशकों को अधिक एन्युटी विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि वे रिटायरमेंट के बाद अपनी जरूरतों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के अनुसार मासिक पेंशन तय कर सकें। इससे आय की स्थिरता और भरोसा दोनों बढ़े हैं। पांचवां बदलाव डिजिटल सुविधाओं को लेकर किया गया है। एनपीएस खाता खोलने, योगदान जमा करने, फंड बदलने और स्टेटमेंट देखने की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और ऑनलाइन बनाया गया है। इससे युवाओं के साथ-साथ दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। छठा सुधार पेंशन फंड मैनेजरों की जवाबदेही और पारदर्शिता से जुड़ा है। निवेशकों को अब अपने निवेश के प्रदर्शन की समय-समय पर स्पष्ट जानकारी मिल रही है, जिससे वे सूझबूझ के साथ फैसले ले सकें। इससे एनपीएस पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

सातवां बड़ा बदलाव वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने के रूप में सामने आया है। उनके लिए दस्तावेजी औपचारिकताओं को कम किया गया है, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। आठवां सुधार स्वैच्छिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब निवेशक अतिरिक्त आय या बोनस मिलने पर आसानी से अतिरिक्त राशि एनपीएस में जमा कर सकते हैं, जिससे भविष्य की पेंशन को और मजबूत बनाया जा सके। नौवां बदलाव असंगठित क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार करने वालों और अस्थायी रोजगार से जुड़े लोगों के लिए नियमों को ज्यादा लचीला बनाया गया है, ताकि वे भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकें। दसवां और अंतिम बड़ा बदलाव यह है कि एनपीएस को एक समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में विकसित किया गया है, जहां निवेश, निकासी, पेंशन और पारदर्शिता चारों पहलुओं को संतुलित किया गया है। इसका उद्देश्य हर नागरिक को सम्मानजनक और सुरक्षित रिटायरमेंट प्रदान करना है। कुल मिलाकर, 2024 में एनपीएस में किए गए ये 10 बड़े बदलाव इस योजना को सिर्फ निवेश का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य की चिंता से मुक्त होने का भरोसेमंद आधार बनाते हैं। बदलते समय और बढ़ती महंगाई के दौर में एनपीएस अब करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा की मजबूत ढाल बनकर उभरा है।

रिटायरमेंट योजना को लेकर युवाओं में भी बढ़ रही रुचि

निजी क्षेत्र में काम करने वाले युवा कर्मचारी, छोटे कारोबारी और स्वरोजगार से जुड़े लोग अक्सर यह सोचकर पेंशन योजनाओं से दूरी बनाए रखते थे कि ये स्कीमें जटिल हैं और लंबे समय तक पैसा फंसा रहता है। 2025 में एनपीएस में किए गए सुधारों के बाद यह धारणा तेजी से बदलती नजर आ रही है। डिजिटल प्रक्रिया के सरल होने से अब एनपीएस खाता खोलना कुछ ही मिनटों का काम रह गया है। मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश, फंड चयन और जानकारी हासिल करना आसान हुआ है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि 28 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं में एनपीएस को लेकर रुचि बढ़ी है। कई युवा इसे अब सिर्फ रिटायरमेंट योजना नहीं, बल्कि दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा का मजबूत आधार मानने लगे हैं। आंशिक निकासी के नियम आसान होने से लोगों का डर भी कम हुआ है। अब उन्हें लगता है कि जरूरत पड़ने पर उनका पैसा पूरी तरह लॉक नहीं रहेगा। यही वजह है कि असंगठित क्षेत्र और छोटे कारोबारियों में भी एनपीएस को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है। कुल मिलाकर, 2025 के बदलावों ने एनपीएस को एक सीमित वर्ग की योजना से निकालकर आम लोगों की जरूरतों से जोड़ दिया है।

बालों के लिए भी फायदेमंद है बद्री गाय का घी

बद्री गाय का घी प्रकृति का दिया एक ऐसा उपहार है जो केवल देवभूमि उत्तराखण्ड में ही पाया जाता है। जिस गाय के दूध से इसका घी बनता है उसे उत्तराखण्ड की कामधेनू के नाम से भी जाना जाता है। ब्रदी गाय हिमालय के लगभग 7000 और उससे ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह गाय चूंकि हिमालय की जड़ी बूटियां और वनस्पतियों का सेवन करती है इसलिए इस गाय के दूध व घी में औषधीय गुणों की भरमार रहती है। कई पुराने वैद्य और चिकित्सक कई असाध्य रोगों के उपचार में इस गाय के घी का इस्तेमाल करते है इसलिए इस घी की डिमांड अन्य घी के मुकाबले ज्यादा रहती है। बद्री घी में ए2 बीटा केसिन प्रोटीन और ओमेगा-3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हृदय और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इस गाय का घी पाचन में हल्का होता है इसलिए इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है। यह घी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता ही है साथ ही इस घी का इस्तेमाल बालों की मालिश करने में किया जाए तो बालों की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाती है। बद्री गाय के घी से रात में बालों की हल्के-हल्के मसाज करने से बालों के टूटने की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। इसके साथ रात में चेहरे को धोकर इस घी से उसकी मसाज की जाए तो वहां पर भी यह कई तरह के फायदे देता है।

अगरबत्ती के धुएं से नहीं बिगड़ेगी सेहत

घर-घर की पूजा-अर्चना, मंदिरों की आरती और ध्यान-साधना की परंपरा से जुड़ी अगरबत्तियों की खुशबू अब आस्था के साथ-साथ सेहत के लिए भी सुरक्षित होगी। लंबे समय से अगरबत्ती के धुएं में मौजूद हानिकारक रसायनों को लेकर उठ रही चिंताओं पर केंद्र सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री प्रल्हाद जोशी ने अगरबत्ती निर्माण के लिए नया राष्ट्रीय मानक जारी किया है, जिसके तहत अब ऐसे रसायनों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह माने जाते हैं। नया मानक पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की शुद्धता सुनिश्चित करेगा, उपभोक्ताओं की सेहत की रक्षा करेगा और भारत को वैश्विक बाजार में और मजबूत स्थिति भी दिलाएगा। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट......

घर-घर में होने वाली पूजा-अर्चना, मंदिरों की आरती और ध्यान-साधना की परंपरा में अगरबत्ती की खुशबू का विशेष महत्व रहा है। आस्था, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाने वाली अगरबत्तियां अब न केवल धार्मिक भावनाओं को सुकून देंगी, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी सुरक्षित होंगी। लंबे समय से अगरबत्ती के धुएं में मौजूद हानिकारक रसायनों को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने एक अहम और दूरगामी कदम उठाया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री प्रल्हाद जोशी ने अगरबत्ती निर्माण के लिए नया भारतीय मानक जारी किया है, जिसे आईएस-19412:2025 नाम दिया गया है। इस मानक के लागू होने से अब अगरबत्तियां आस्था के साथ-साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल भी होंगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक और निर्यातक देश है। देश में करीब आठ हजार करोड़ रुपये का यह उद्योग लाखों कारीगरों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को रोजगार देता है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह उद्योग आजीविका का एक मजबूत आधार माना जाता है। ऐसे में अगरबत्ती निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम न केवल उपभोक्ताओं के हित में हैं, बल्कि उद्योग को भी नई मजबूती देने वाले हैं। सरकार का मानना है कि नए मानक से अगरबत्तियों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग और साख मजबूत होगी। यह नया मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अगरबत्ती निर्माण प्रक्रिया को शुद्ध, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। सनातन परंपरा में अगरबत्ती को शुद्धता, सकारात्मक ऊर्जा और वातावरण को पवित्र करने का साधन माना गया है। ऐसे में पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में यदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों की मिलावट हो, तो यह न केवल उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है, बल्कि आस्था के मूल भाव के भी खिलाफ है। नए मानक के तहत बीआइएस का मानक चिह्न अगरबत्तियों पर भरोसे की पहचान बनेगा। इससे उपभोक्ताओं को यह भरोसा मिलेगा कि जिस अगरबत्ती का उपयोग वे पूजा या साधना में कर रहे हैं, उसकी खुशबू सेहत पर भारी नहीं पड़ेगी। पिछले कुछ वर्षों में देश और विदेश में हुए कई अध्ययनों में यह बात सामने आई थी कि कुछ अगरबत्तियों में कृत्रिम रसायन और कीटनाशक मिलाए जा रहे हैं। इन रसायनों से निकलने वाला धुआं सांस के जरिये शरीर में प्रवेश कर एलर्जी, आंखों में जलन, सिरदर्द, सांस की तकलीफ और अन्य गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। खासकर बंद कमरों में लंबे समय तक अगरबत्ती जलाने से इनडोर हवा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। लगातार दूषित हवा के संपर्क में रहने से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अधिक खतरा रहता है। इन्हीं कारणों से यूरोप समेत कई देशों में सुगंधित उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायनों पर पहले ही सख्त पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। अब भारत में भी इन्हीं वैश्विक अनुभवों और वैज्ञानिक निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अगरबत्ती निर्माण में खतरनाक रसायनों पर रोक लगाई गई है। नए मानक के तहत अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, खुशबू, जलने की गुणवत्ता और शुद्धता से जुड़े स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। मशीन से बनी, हाथ से बनी और पारंपरिक मसाला अगरबत्तियों-तीनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश बनाए गए हैं, ताकि हर प्रकार की अगरबत्ती सुरक्षित और मानक के अनुरूप हो। इससे न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद मिलेगा, बल्कि कारीगरों और निर्माताओं को भी गुणवत्ता सुधारने का अवसर मिलेगा। इस मानक के सबसे अहम पहलुओं में हानिकारक रसायनों पर पूरी तरह प्रतिबंध शामिल है। अब अगरबत्ती निर्माण में उन रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जो अब तक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा बने हुए थे। इनमें मुख्य रूप से कीड़े मारने की दवाएं शामिल हैं, जिनका धुआं सांस के जरिये शरीर में जाकर कई बार सिगरेट से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ सकता है। प्रतिबंधित किए गए रसायनों में एलेथ्रिन, पर्मेथ्रिन, सायपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन और फिप्रोनिल जैसे तत्व शामिल हैं। ये रसायन तेज और लंबे समय तक टिकने वाली खुशबू के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन इनके दुष्प्रभाव अब सामने आ चुके हैं। इसके अलावा सायनाइड, एथिल एक्रिलेट और डाइफेनाइलअमाइन जैसे रसायनों के धुएं से सिरदर्द, एलर्जी और सांस संबंधी समस्याएं होने की आशंका रहती है। नए मानक के तहत इन सभी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस पहल का मकसद केवल उद्योग को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि आस्था की रक्षा के साथ-साथ आम लोगों की सेहत को सुरक्षित करना है। शास्त्रों और परंपराओं में भी पूजा के लिए शुद्ध सामग्री के उपयोग पर जोर दिया गया है। अगरबत्ती का मूल उद्देश्य वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाना है, न कि उसे प्रदूषित करना। नया भारतीय मानक इसी भावना के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि पूजा-पाठ और साधना का अनुभव सुरक्षित, सुकून देने वाला और स्वास्थ्य के अनुकूल बने। अगरबत्ती के लिए जारी किया गया यह नया राष्ट्रीय मानक आस्था और विज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मानक लोगों की सेहत की रक्षा के साथ परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु भी बनेगा।

जब सुविधा पड़ने लगे 'जान' पर भारी

हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां सुविधा की परिभाषा धैर्य नहीं, बल्कि जल्दबाजी बन चुकी है। घर की रसोई में अगर आज नहीं तो कल तक चल जाने वाला राशन अब 'अभी चाहिए' की मानसिकता में बदल दिया गया है। सच्चाई यह है कि न रोटी आज ही खत्म हो रही होती है और न ही चूल्हा बुझने वाला होता है, फिर भी बाजार ने हमारे भीतर यह डर बैठा दिया है कि अगर सामान 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो जिंदगी थम जाएगी। इसी मानसिकता से जन्म लिया है '10 मिनट में ग्रॉसरी आपके द्वार' जैसे खतरनाक कॉन्सेप्ट ने जो सुविधा कम और जोखिम ज्यादा बनता जा रहा है। इस सुविधा की कीमत अब डिलीवरी ऐप्स के बाइक राइडर अपनी जान देकर चुका रहे हैं, और अनजाने में आम लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। 10 मिनट की डिलीवरी के दबाव में शहरों की सड़कों पर दौड़ती बाइकें अब समय से नहीं, मौत से होड़ लगाने लगी हैं। रेड लाइट जंप करना, ओवरस्पीडिंग, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी। यह सब किसी लापरवाही का नहीं बल्कि उस सिस्टम का नतीजा है जो इंसान से ज्यादा ऐप की रेटिंग, इंसेंटिव और टाइमर को अहमियत देता है। देहरादून जैसे शांत शहरों में भी यह खतरा अब रोजमर्रा की हकीकत बन चुका है। हाल की एक घटना में 10 मिनट की डिलीवरी के दबाव में तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि जान बच गई, लेकिन सवाल यह है कि अगली बार किसकी बारी होगी? अगर उस बाइक राइडर पर समय का ऐसा जानलेवा दबाव न होता, तो क्या वह इतनी बेतहाशा रफ्तार में होता? आज जरूरत इस बात की है कि हम खुद से पूछें, क्या हमें सच में 10 मिनट में ग्रॉसरी चाहिए? क्या यह सुविधा हमारी और दूसरों की जान से ज्यादा कीमती है? जब सुविधा इंसान से ऊपर रखी जाने लगे, तब वह सुविधा नहीं, खतरा बन जाती है। यही कारण है कि यह मुद्दा अब सिर्फ बाजार या ऐप्स का नहीं रहा, बल्कि समाज और सरकार दोनों के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुका है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां जरूरत और जल्दबाजी के बीच की रेखा धीरे-धीरे मिटती जा रही है। घर की रसोई में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि राशन खत्म होने से कई दिन पहले ही चिंता शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि अगर आज सामान नहीं आया तो शाम का खाना नहीं बनेगा। इसी चिंता के चलते काम से लौटता व्यक्ति किराना दुकान से सामान लेकर ही घर आता है। जबकि सच्चाई यह होती है कि घर में अभी भी कई दिनों का राशन मौजूद रहता है। यह बात महिला और पुरुष-दोनों अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मन में यह दबाव बना रहता है कि जिस दिन कहा गया है, उसी दिन सामान घर पहुंचना चाहिए। सवाल यहीं से जन्म लेता है कि जब रसोई के सामान की वास्तव में इतनी आपात आवश्यकता नहीं होती, तो फिर "10 मिनट में ग्रॉसरी आपके द्वार" जैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत किसे पड़ी और क्यों पड़ी? पिछले कुछ वर्षों में ई-कॉमर्स क्षेत्र ने जिस तेजी से विस्तार किया है, उसने खरीदारी की आदतों को पूरी तरह बदल दिया है। एक समय था जब अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां एक या दो दिन में सामान की डिलीवरी को बड़ी सुविधा के रूप में पेश करती थीं। उपभोक्ता भी उसी में संतुष्ट थे। लेकिन अब उसी बाजार में क्विक-कॉमर्स का दौर आ गया है। ब्लिंकिट, जेप्टो और इसी तरह के कई ऐप्स यह दावा कर रहे हैं कि वे किसी भी तरह का सामान, खासकर रोजमर्रा की ग्रॉसरी, महज 10 मिनट में घर पहुंचा सकते हैं। तकनीकी रूप से यह संभव भी हो रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई और इसकी कीमत पर अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ग्रॉसरी की 10 मिनट में डिलीवरी किसे चाहिए? क्या उपभोक्ता को इससे कोई ऐसा बड़ा लाभ मिल रहा है, जिसके बिना जीवन ठहर जाए? या फिर यह केवल बाजार द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम जरूरत है, जिसे धीरे-धीरे लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है? इन ऐप्स के जरिए बड़ी-बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने हजारों युवाओं को रोजगार तो दिया है, लेकिन किस तरह का रोजगार यह भी सोचने वाली बात है। अधिकांश डिलीवरी राइडर आज एक तरह से दिहाड़ी मजदूर बनकर रह गए हैं, जिन्हें पूरे दिन ऐप से मिलने वाले टास्क पूरे करने होते हैं। उनका काम केवल पैकेट उठाना और तय समय सीमा के भीतर उसे किसी भी हाल में ग्राहक तक पहुंचाना बन गया है। शुरुआत में लोगों को 10 मिनट की डिलीवरी का यह कॉन्सेप्ट आकर्षक लगा। लगा कि समय की बचत हो रही है, सुविधा बढ़ रही है। लेकिन अब धीरे-धीरे इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यह सुविधा अब जान पर आफत बनती जा रही है। 10

'10 मिनट में डिलीवरी' पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में खतरनाक होंगे परिणाम

क्विक-कॉमर्स के नाम पर 10 मिनट में डिलीवरी का चलन देश के कई शहरों में तेजी से फैलता जा रहा है। शुरुआत में इसे सुविधा और तकनीकी प्रगति के रूप में देखा गया, लेकिन अब इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस मॉडल पर समय रहते ठोस नियंत्रण नहीं किया, तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। सड़क सुरक्षा से लेकर श्रमिक अधिकारों तक, यह मुद्दा अब एक बड़ी राष्ट्रीय चिंता बनता जा रहा है। शहरी इलाकों में ट्रैफिक पहले ही अव्यवस्थित है। ऐसे में 10 मिनट की डिलीवरी का दबाव सड़कों पर जोखिम को कई गुना बढ़ा रहा है। तेज रफ्तार बाइक, ट्रैफिक सिग्नलों की अनदेखी और समय से पहले पहुँचने की हड़बड़ी अब आम दृश्य बनते जा रहे हैं। कई जगहों पर क्विक-कॉमर्स डिलीवरी से जुड़े हादसों में बढ़ोतरी की बात सामने आई है। अगर यही रफ्तार बनी रही, तो दुर्घटनाओं की संख्या और गंभीरता दोनों बढ़ सकती हैं। डिलीवरी राइडरों की स्थिति भी चिंता का विषय है। ऐप आधारित सिस्टम में रेटिंग और इंसेंटिव का ऐसा दबाव बनाया गया है कि राइडर अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हो जाते हैं। समय पर डिलीवरी न होने की स्थिति में उनके काम और कमाई पर सीधा असर पड़ता है। नतीजा यह होता है कि वे ओवरस्पीडिंग और नियम तोड़ने जैसे कदम उठाते हैं। यह व्यवस्था श्रमिकों के शोषण की ओर इशारा करती है। राज्यों के ट्रैफिक विभाग लगातार रैश ड्राइविंग को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन क्विक-कॉमर्स का यह मॉडल उन प्रयासों को कमजोर कर रहा है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस पर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं बनातीं, तो कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर इसका असर और गहरा होगा। कुछ राज्यों में इस विषय पर शुरुआती चर्चा जरूर शुरू हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नीति सामने नहीं आई है। सामाजिक स्तर पर भी इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आम नागरिक, पैदल यात्री और दोपहिया वाहन चालक इस जल्दबाजी का सबसे आसान शिकार बनते हैं। अगर समय रहते इस पर रोक या सख्त नियम नहीं बनाए गए, तो सुविधा के नाम पर देशभर में असुरक्षा का माहौल बढ़ सकता है। सरकार को न्यूनतम डिलीवरी समय तय करने, कंपनियों की जवाबदेही तय करने और राइडरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कदम तुरंत उठाने चाहिए। अन्यथा 10 मिनट की यह दौड़ आने वाले समय में न केवल सड़कों पर, बल्कि पूरे समाज पर भारी पड़ सकती है।

मिनट में डिलीवरी पूरी करने के दबाव ने शहरों की सड़कों को और अधिक खतरनाक बना दिया है। आए दिन क्विक-कॉमर्स ऐप्स के बाइक राइडरों के हादसे सामने आ रहे हैं। तेज रफ्तार, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और समय से पहले पहुंचने की हड़बड़ी इन सबने दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ा दी है। एक तरफ राज्य सरकारें शहरों में रैश ड्राइविंग पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं, चालान और सख्ती की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ 10 मिनट की डिलीवरी का यह मॉडल उन तमाम प्रयासों पर पानी फेरता दिखाई देता है। देहरादून जैसे शहर, जिसे अब मेट्रो सिटी की श्रेणी में गिना जाने लगा है, वहां भी यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। सरकार लगातार लोगों को तेज रफ्तार वाहन चलाने के खतरों से आगाह कर रही है, लेकिन दूसरी ओर क्विक-कॉमर्स ऐप्स के बाइक राइडर समय के दबाव में नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हाल ही में देहरादून में घटी एक घटना इस खतरे की गंभीरता को साफ तौर पर सामने लाती है। 10 मिनट की डिलीवरी के दबाव में तेज रफ्तार से जा रहे एक बाइक राइडर ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। महिला ने बाकायदा इंडिकेटर देकर सड़क पार करने का संकेत दिया था, फिर भी बाइक सवार इतनी तेजी में था कि वह समय पर ब्रेक तक नहीं लगा सका। सौभाग्य से महिला को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह केवल किस्मत का खेल था। सवाल यह है कि अगर उस बाइक राइडर पर समय का इतना दबाव न होता, तो क्या वह इतनी लापरवाही से वाहन चला रहा होता? यहीं से यह बहस और गहरी हो जाती है कि 10 मिनट में डिलीवरी का यह कॉन्सेप्ट आखिर किसके लिए बनाया गया है। क्या इससे ग्राहक को कोई ऐसा ठोस लाभ हुआ है, जो उसकी सुरक्षा से बड़ा हो? क्या इससे डिलीवरी का काम करने वाले बाइक राइडरों की आर्थिक स्थिति में कोई वास्तविक सुधार आया है? क्या 10 मिनट में मिलने वाली ग्रॉसरी, पास के स्टोर से मिलने वाली ग्रॉसरी की तुलना में सस्ती है? या फिर सच्चाई यह है कि न तो ग्राहक को कोई बड़ा आर्थिक फायदा मिल रहा है और न ही राइडर की जिंदगी आसान हो रही है। असल में नुकसान कई स्तरों पर हो रहा है। सबसे पहले, डिलीवरी राइडर लगातार मानसिक दबाव में जी रहा है। उसे हर पल यह डर सताता रहता है कि अगर वह समय पर डिलीवरी नहीं कर पाया तो उसकी रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप उसे लॉग आउट कर देगा या फिर उसकी आईडी ही ब्लॉक कर दी जाएगी। यही डर उसे ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करने और जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर करता है। दूसरी ओर, सड़क पर चलने वाला आम आदमी भी इस जल्दबाजी का शिकार बन रहा है, जो पूरी सावधानी के बावजूद किसी तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आ सकता है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने भी संसद में चिंता जताई है। उन्होंने राज्यसभा में इस 10 मिनट की डिलीवरी के खतरनाक कॉन्सेप्ट को लेकर सरकार को चेताया और कहा कि यह ट्रेंड डिलीवरी राइडरों की जान को गंभीर खतरे में डाल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि समय पर रुकने, जैसे लाल बत्ती पर रुकने तक की स्थिति में डिलीवरी बॉय को नुकसान का डर सताने लगता है, जिसके चलते वह नियम तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। सांसद ने सरकार से इस कॉन्सेप्ट पर रोक लगाने और राइडरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। 10 मिनट की डिलीवरी का यह मॉडल अब केवल सुविधा का मुद्दा नहीं रह गया है। यह सड़क सुरक्षा, श्रमिक अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सुविधा को हम प्रगति मान रहे हैं, वही हमारे लिए खतरे का कारण बनती जा रही है। क्योंकि आप भले ही संभलकर गाड़ी चलाएं, लेकिन अगर सामने से आने वाला व्यक्ति समय के दबाव में बेतहाशा रफ्तार से आ रहा हो, तो दुर्घटना से बच पाना हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। यही वह सच्चाई है, जिसे नजरअंदाज करना अब और भी भारी पड़ सकता है।

पुलिस अभिरक्षा में हुए हमले में दुर्दान्त अपराधी विनय त्यागी ढेर

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से डरे गैंगेस्टर संरक्षण लेने के लिए उत्तराखंड की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन यहां भी उनको पनाह की जगह मौत मिल रही है। इसकी बानगी लक्सर में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी विनय त्यागी उत्तराखंड में पनाह लेने के लिए देहरादून में एक मामूली चोरी के आरोप में जेल चला जाता है। लेकिन पेशी पर ले जाते समय प्रतिद्वंदी अपराधियों द्वारा रास्ते में घात लगाकर हमला करके उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। इससे यह तो संदेश चला ही गया कि देवभूमि अपराधियों के लिए संरक्षण स्थल नहीं है।

उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में बुधवार 24 दिसंबर को उस समय सनसनी फैल गई, जब कुख्यात बदमाश विनय त्यागी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। जिस समय यह घटना घटी, उस समय विनय त्यागी को रुड़की जेल से पेशी के लिए लक्सर ले जाया जा रहा था। बता दें कि कुख्यात बदमाश विनय त्यागी मेरठ के मेडिकल थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है। इस ताबड़तोड़ गोलीबारी में विनय त्यागी को दो गोलियां गलीं, जबकि पुलिस सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए। गोलीबारी की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुड़की कारागार में बंद मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव खाईखेड़ी निवासी कुख्यात बदमाश विनय त्यागी की धोखाधड़ी के एक मामले में बुधवार को लक्सर एसीजेएम कोर्ट में पेशी थी। कारागार से चालक सहित छह पुलिसकर्मी सरकारी वाहन में उसे पेशी पर ला रहे थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी लक्सर के रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंची तो वहां पहले से ही जाम लगा हुआ था। इस क्षेत्र में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा में तैनात दो पुलिस कर्मी एवं एक दरोगा जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे थे कि पास ही पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना भीषण था कि कुछ ही देर में मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। गाड़ी में मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए स्थिति को संभाला। अचानक हुए इस हमले में अपराधी विनय त्यागी और दो पुलिस कर्मी घायल हो गए। विनय त्यागी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बदमाश विनय त्यागी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। जहां इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। घायल पुलिसकर्मियों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हमले की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे जिले में नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। हमले के दौरान लापरवाही बरतने पर एक दारोगा व दो सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वारदात के दौरान बहादुरी का परिचय देते हुए घायल विनय त्यागी को अस्पताल पहुंचाने पर एसएसपी ने हेड कांस्टेबल गज्जीलाल और वाहन चालक कांस्टेबल संदीप सिंह को शाबाशी भी दी। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि हेड कांस्टेबल और वाहन चालक की मुस्तैदी से विनय त्यागी की जान बची है। दोनों पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा।

पुलिस ने सघन अभियान चलाकर मात्र 24 घंटे में विनय त्यागी पर सुनियोजित हमला करने वाले सनी यादव और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। सनी यादव उर्फ शेरा के खिलाफ लूट व हत्या के कुछ मुकदमें भी दर्ज हैं, काशीपुर डकैती में जमानत पर छूटकर 2012 में नौकरी करने मेरठ पहुंचे सनी यादव ने विनय त्यागी के लिए रंगदारी के लिए काल करने, रकम वसूली का काम शुरू किया था।

कौन है विनय त्यागी

मुजफ्फरनगर के खाईखेड़ी गांव के गैंगस्टर विनय त्यागी उर्फ टिंकू पर यूपी और उत्तराखंड के विभिन्न थानों में 57 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी का मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और देहरादून में प्रॉपर्टी के विवादित मामलों में दखल रहा। अपराध की काली दुनिया के बाद वह सियासत में भी छा जाने का ख्वाब देखता था। उसने अपनी पत्नी को दो बार पुरकाजी ब्लॉक से प्रमुख भी बनवा दिया। सहारनपुर की देवबंद सीट से खुद भी एकबार विधानसभा का चुनाव लड़ा।

मृतक अपराधी विनय त्यागी उर्फ टिंकू के पिता सेवाराम त्यागी मेरठ में नौकरी करते थे। वहीं पर विनय त्यागी की पढ़ाई भी हुई। अपराध की राह पकड़ी तो साल 1996 में खाईखेड़ी में प्रेम-प्रसंग को लेकर हुए विवाद के बाद संदीप उर्फ टोनी और उसके बहनोई गाजियाबाद के पिलखुआ निवासी प्रदीप की हत्या में विनय त्यागी का नाम आया, उस समय विनय 16 वर्ष का था। मुजफ्फरनगर जिले में छपार, पुरकाजी, नई मंडी थाने में आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। सितंबर में विनय त्यागी देहरादून अपने एक तथाकथित परीचित डॉ त्यागी के यहां आया। 14 सितंबर को डॉ. त्यागी ने विनय त्यागी के खिलाफ अपनी गाड़ी से सामान चोरी होने का मुकदमा लिखवाया था। पुलिस ने 13 अक्तूबर को विनय त्यागी उर्फ टिंकू को गिरफ्तार कर लिया। 30 अक्तूबर को विनय की जमानत अर्जी देहरादून में खारिज कर दी गई थी। विनय त्यागी अन्य मामलों में भी आरोपित था, जिस कारण वह रुड़की जेल में बंद था।

सरस्वती साधकों का तीर्थ बना लेखक गांव

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

मेरे साहित्यिक मित्र एवं देश के शिक्षा मंत्री व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे डॉ रमेश पोखरियाल निशंक के 'लेखक गांव' चलने के आग्रह को टाल नही सका। ज्योतिष विद्वान पंडित रमेश सेमवाल इसका माध्यम बने और हम ब्रह्माकुमारीज केंद्र से ही सीधे लेखक गांव के लिए प्रस्थान कर गए। इससे पहले मैंने कभी प्रत्यक्ष रूप में इस गांव को देखा नही था, हालांकि बडे भाई डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने 'लेखक गांव' को लेकर मेरे सामने 'देश के महान साहित्यकार एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी' की लेखकों के प्रति सम्मान सोच को साकार करते हुए जो शब्द चित्र में उकेरे थे, उससे यह निश्चित हो गया था कि एक ऐसे लेखक गांव ने जन्म लिया है, जहां ज्ञान की देवी सरस्वती अपने पुत्रों के माध्यम से निर्बाध अपनी उपस्थिति का एहसास कराएगी। देहरादून से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देश में अपनी तरह के इस पहले 'लेखक गांव' का उद्घाटन बीते वर्ष 24 नवंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल ले जन गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यहां तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्य, कला और संस्कृति महोत्सव भी मनाया गया। उदघाटन समारोह में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी तथा लेखिका ममता कालिया जैसे अनेक दिग्गज भी आए थे, वही 65 से अधिक देशों के लेखन, कला और संस्कृति से जुड़े लोग इस भव्य एवं दिव्य साहित्यिक महोत्सव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे। जिनमें साहित्यिक जिज्ञासु छात्रों की भी भागीदारी रही। देहरादून के जोलीग्रांट हवाई अड्डे के निकट सुरम्य हिमालयी क्षेत्र थानो में यह 'लेखक गांव' विकसित किया गया है, जहां

लेखकों, साहित्यकारों, पत्रकारों व विचारकों को अपनी कृतियों के सृजन के लिए शांत एवं रचनाशील वातावरण सहजता से उपलब्ध है। मुझे याद है मेरे प्रेरक पद्मश्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर अपनी साहित्यिक रचनाओं को जन्म देने के लिए अक्सर मसूरी प्रवास करते थे, जहां मां सरस्वती की अनुभूति से उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। ऐसा ही सुखद वातावरण लेखक गांव में भी देखने को मिलता है। लेखक गांव के एक प्रवेश द्वार पर भगवान धन्वंतरि की विशाल अष्टधातु प्रतिमा और दूसरे प्रवेश द्वार पर भगवान नरसिंह का सुंदर कलात्मक मंदिर आगन्तुकों का मन मोह लेता है।लकड़ी की नक्काशी के साथ सुसज्जित किए गए मंदिर को मिलती विशाल वृक्ष की छांव मुसाफिर के कदम भी सहज ही रोक देती है। डॉ निशंक ने दिखाया कि इसी मंदिर परिसर में बनाये गए चबूतरे लेखकों के मन के आवेगों को गति देंगे और एक नए सृजन की राह बनेगी। मंदिर के शीर्ष की तरफ भगवान शिव का जलाभिषेक करती प्रकृति को साकार किया जा रहा है। लेखन, संस्कृति, प्रकृति और कला से जुड़े विषयों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श के केंद्र बने इस 'लेखक गांव' में नालन्दा पुस्तकालय जिसमे फिलहाल 50 हजार पुस्तकें सुसज्जित की गई है, के पठनीय वातावरण से हर कोई आकर्षित हो रहा है, वही पुस्तकालय के प्रथम तल पर भव्य ऑडिटोरियम जिसे रंग शाला भी कह सकते है मानकों के अनुरूप बनी है। महाकवि कालीदास, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसी कालजयी हस्तियों का उल्लेख करते हुए लेखक गांव के जन्मदाता डॉ निशंक बताते है कि 'हिमालय हमेशा उनकी प्रेरणा का केंद्र रहा है और इस धरती में कोई तो ऐसी बात है कि लोगों ने यहां से प्रेरणा लेकर दुनिया में अपना नाम किया। उन्होंने लेखक गांव में पुस्तकालय के साथ-साथ ध्यान-योग केंद्र, हिमालयी संग्रहालय, संजीवनी रसोई, नक्षत्र वाटिका, ग्रह वाटिका भी दिखाई। वही जैन वाटिका में विभिन्न प्रजातियों के पौधों के इतिहास व परिचय के लिए बारकोड व्यवस्था की गई है।

यहां बनाई गई लेखन कुटीर अनुपम है, इस कुटीर में रहकर लेखक अपनी सृजनशीलता को श्रेष्ठतम रूप दे सकते है और देश व समाज के लिए अच्छा साहित्य सामने ला सकते है। 'लेखक गाँव' का उद्देश्य देश-दुनियाँ के उन विलक्षण, विद्वान साहित्यकारों, गीतकारों, कलाकारों को एक ठौर यानि ठिकाना प्रदान करना है, जिनकी लेखनी ने अपने समय की कालजयी रचनाओं का सृजन कर आमजन के बीच लोकप्रियता हासिल की है। यह गांव हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगा, ऐसा माना जा सकता है। अभी 'लेखक गांव' की निर्माणता गतिमान है, इसलिए इसकी पूर्ण रमणीकता का तभी सुखानन्द लिया जा सकता है, जब यह पूर्णता को प्राप्त हो, तब तक इसके लिए हम अपने सरस्वती पुत्र डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को शुभकामनाएं तो दे ही सकते है।

— गुरु गोविन्द सिंह —

हिन्दू धर्म और संस्कृति के रक्षक

ललित गर्ग

भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायी है। वे केवल सिख धर्म के दसवें गुरु ही नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा, दार्शनिक, समाज-सुधारक, हिन्दू धर्म-संस्कृति के रक्षक और राष्ट्र-चेतना के जाग्रत प्रतीक थे। उनकी महान् तपस्वी, महान् कवि, महान् योद्धा, महान् संत सिपाही साहिब आदि स्वरूपों में पहचान होती है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती केवल एक ऐतिहासिक तिथि नहीं, बल्कि मानवता को साहस, न्याय, आत्मसम्मान और धर्मरक्षा का संदेश देने वाला पर्व है। उनकी जीवन-यात्रा अन्याय के प्रतिकार, सत्य की स्थापना और मानव गरिमा की रक्षा के लिए समर्पित रही। वे संपूर्ण भारतीय समाज के आस्था के केंद्र हैं, उनके जीवन से हमें राष्ट्रप्रेम और मानवतावादी धर्म की प्रेरणा मिलती है।

गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब (वर्तमान बिहार) में हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नौवें गुरु थे, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पिता के इस अद्वितीय त्याग ने गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। बहुत कम आयु में ही उन्होंने यह समझ लिया कि धर्म केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी है। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष, तपस्या और सेवा का अद्भुत संगम रहा। उन्होंने धर्म को कर्म से जोड़ा और आध्यात्मिकता को सामाजिक उत्तरदायित्व का रूप दिया। उनका स्पष्ट संदेश था कि सच्चा धर्म वह है जो निर्बलों की रक्षा करे, अत्याचार का विरोध करे और मानव को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाए। वे कहते थे कि भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर

चलना ही सच्ची भक्ति है।

1699 में बैसाखी के पावन अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर इतिहास की दिशा ही बदल दी। खालसा का अर्थ है-शुद्ध, निर्भीक और समर्पित जीवन। उन्होंने पाँच प्यारे बनाकर समानता, भाईचारे और त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। खालसा की दीक्षा के माध्यम से उन्होंने जाति, वर्ग और ऊँच-नीच के भेद को समाप्त कर दिया। उन्होंने खालसा पंथ के अनुयायियों को पंच ककार केश, कड़ा, कंघा, कृपाण, कच्छा धारण करने का निर्देश दिया। ये शौर्य, शुचिता तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के संकल्प के प्रतीक हैं। गुरु ने सिखाया कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और सबका सम्मान समान है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं का केंद्रबिंदु साहस और करुणा का संतुलन है। वे एक ओर शस्त्र धारण करने की प्रेरणा देते हैं, तो दूसरी ओर दया, प्रेम और सेवा को जीवन का आधार बताते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन-"जब सब उपाय विफल हो जाएँ, तब धर्म के लिए तलवार उठाना न्यायोचित है"-यह स्पष्ट करता है कि हिंसा उनका उद्देश्य नहीं थी, बल्कि अत्याचार के विरुद्ध अंतिम विकल्प थी। गुरु गोविंद सिंह भारतीय जीवन मूल्यों की रक्षा और समाज को नए सिरे से संगठित एवं सशक्त करने वाले एक महापुरुष हैं, उनका व्यक्तित्व अलौकिक, साहसी एवं भारतीयता से ओतप्रोत था। उन्होंने आनंदपुर का सुख, माता पिता की छांव और बच्चों का मोह छोड़कर धर्म रक्षा का मार्ग चुना। उन्होंने दमन, अन्याय, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद 11 नवंबर 1675 को नौ साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह सिखों के दसवें गुरु बने। दुनिया में देश व धर्म की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महापुरुष तो अनेक मिलेंगे किन्तु अपनी तीन पीढ़ियों, बल्कि यों कहें कि अपने पूरे वंश को इस पुनीत कार्य हेतु बलिदान करने वाले विश्व में शायद एकमेव महापुरुष गुरु गोविन्द सिंहजी ही है। जिन्होंने त्याग, बलिदान एवं कर्तृत्ववाद का संदेश दिया। भाग्य की रेखाएं स्वयं निर्मित की। स्वयं की अनन्त शक्तियों पर भरोसा और आस्था जागृत की। सभ्यता और संस्कृति के प्रतीकपुरुष के रूप में जिन्होंने एक नया जीवन-दर्शन दिया, जीने की कला सिखलाई। जिनको बहुत ही श्रद्धा व प्यार से कलगीयां, सरबंस दानी, नीले वाला, बाला प्रीतम, दशमेश पिता आदि नामों से पुकारा जाता है। भारत में फैली दहशत, डर और जनता का हारा हुआ मनोबल देखकर उन्होंने कहा ''मैं एक ऐसे पंथ का सृजन करूँगा जो सारे विश्व में विलक्षण होगा। जिससे मेरे शिष्य संसार के असंख्य लोगों में पहली ही नजर में पहचाने जा सकेंगे। जैसे हिरनों के झुंड में शेर और बगुलों के झुंड में हंस। वह केवल बाहर से अलग न दिखे बल्कि आंतरिक रूप में भी ऊँचे, साहसी और सच्चे विचारों वाले हो।

गुरु गोविंद सिंह एक महान कवि और विद्वान भी थे। उनकी रचनाएँ 'दसम ग्रंथ' में संकलित हैं, जिनमें वीर रस, भक्ति, नीति और दर्शन का अद्भुत समन्वय मिलता है। उनकी कविताएँ आत्मबल जगाती हैं और जीवन में धर्म व मर्यादा का बोध कराती हैं। उन्होंने भाषा, साहित्य और संस्कृति के माध्यम से समाज में जागरण का कार्य किया। उनका पारिवारिक जीवन भी त्याग और बलिदान की अनुपम गाथा है। उनके चारों पुत्र-साहिबजादे, धर्म और सत्य की रक्षा करते हुए शहीद हुए। छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया, फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर मानवता को यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए व्यक्तिगत दुख भी स्वीकार्य है। यह जीवन-चरित्र मानव इतिहास में दुर्लभ

उदाहरण है।

गुरु गोविंद सिंह जी ने न केवल सिख समुदाय, बल्कि संपूर्ण मानवता को आत्मसम्मान और निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने स्त्रियों को समान सम्मान दिया और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उनका जीवन बताता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति समाज से पलायन नहीं करता, बल्कि समाज को न्यायपूर्ण बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। उनका एक अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय था-गुरुगद्दी को किसी व्यक्ति के स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को सौंपना। इससे उन्होंने यह स्पष्ट किया कि गुरु का स्वरूप शाश्वत ज्ञान है, न कि देह। यह निर्णय लोकतांत्रिक चेतना, विनम्रता और आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रतीक है। आज जब विश्व हिंसा, असहिष्णुता, भेदभाव और नैतिक संकटों से जूझ रहा है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएँ पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। वे हमें सिखाते हैं कि साहस के बिना सत्य अधूरा है और करुणा के बिना शक्ति विनाशकारी। उनका जीवन संतुलित, मूल्यनिष्ठ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है।

गुरु गोविन्द सिंहजी का जीवन एक कर्मवीर की तरह था। भगवान श्रीकृष्ण की तरह उन्होंने भी समय को अच्छी तरह परखा और तदनुसार कार्य आरम्भ किया। उनकी प्रमुख शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य, नशामुक्त जीवन, युद्ध-विद्या, सदा शस्त्र पास रखने और हिम्मत न हारने की शिक्षाएँ मुख्य हैं। उनकी नजर में सत्ता से ऊंचा स्वराष्ट्र, स्व-अस्तित्व, समाज एवं मानवता का हित सर्वोपरि था। यूं लगता है वे हिन्दू जीवन-दर्शन के पुरोधा बन कर आए थे। उनकी इच्छा थी कि प्रत्येक भारतवासी सिंह की तरह एक प्रबल प्रतापी जाति में परिणत हो जाये और भारत का उद्धार करें। गुरु गोविन्द सिंह जैसे महापुरुष इस धरती पर आये जिन्होंने सबको बदल देने का दंभ तो नहीं भरा पर अपने जीवन के साहस एवं शौर्य से डर एवं दहशत की जिन्दगी को विराम दिया। उनके कारण ही हिन्दू अपने अस्तित्व एवं अस्मिता को कायम रख पाये। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर देश और दुनिया के लिए उनका संदेश स्पष्ट है-डरो मत, झुको मत और अन्याय के सामने कभी समझौता मत करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, पर उसका प्रयोग सदैव धर्म, मानवता और न्याय के लिए करो। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ईश्वर स्वयं शक्ति देता है। आज आवश्यकता है कि हम उनकी शिक्षाओं को केवल स्मरण न करें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। सत्यनिष्ठा, सेवा, साहस, समानता और त्याग-यदि ये मूल्य हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाएँ, तो समाज में स्वतः ही शांति और सद्भाव का वातावरण निर्मित होगा। उनकी जयंती हमें यह संकल्प लेने का अवसर देती है कि हम एक ऐसे विश्व के निर्माण में सहभागी बनें, जहाँ भय नहीं, बल्कि न्याय का शासन हो। उनका जीवन दीपस्तंभ की तरह है, जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। उनकी शिक्षाएँ समय, देश और सीमाओं से परे हैं।

अंकिता का मामला राजनीति से ऊपर इंसानियत का प्रश्न है: यशपाल आर्य

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि, जब सत्ता, पैसे और रसूख का अनैतिक गठजोड़ होता है, तब आम जनता की बेटियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी? उन्होंने कहा कि, अंकिता हत्याकांड में भाजपा से जुड़े लोगों के माध्यम से जो नए तथ्य आए हैं उन्होंने देवभूमि के जनमानस को झकझोरकर रख दिया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, हत्यारे और हत्याकांड के कारक सीधे तौर पर भाजपा व सरकार के ताकतवर लोगों से जुड़े थे इसलिए अंकिता के परिवार, कांग्रेस और उत्तराखंड की जनता की पुरजोर मांग पर भी अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं हुई।

श्री आर्य ने कहा कि नए तथ्यों से साफ हो गया है कि, अंकिता भंडारी की हत्या न कोई दुर्घटना थी, और न ही यह किसी एक व्यक्ति की मानसिक विकृति का मामला था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, यह सत्ता-संरक्षित दरिंदगी का उदाहरण था, जहाँ उत्तराखण्ड की एक बेटी ने सत्ता की दरिंदगी के आगे झुकने से इनकार किया। अंकिता को अपनी अस्मिता का सौदा न करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी।

यशपाल आर्य ने पूछा कि, जो लोग संस्कार, धर्म, मर्यादा और संस्कृति की ठेकेदारी करते हैं, उनके राज में ही बेटियाँ सबसे ज्यादा असुरक्षित क्यों हैं? उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य कारण भाजपा संगठन से जुड़े अति विशिष्ट व्यक्ति को स्पेशल सर्विस देने का दबाव था। उन्होंने आरोप लगाया कि, राज्य की भाजपा सरकार द्वारा गठित एस.आई.टी. ने उस कथित अति विशिष्ट व्यक्ति को जांच के दायरे से बाहर रखा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, अब भाजपा जाति का सहारा लेकर उस अतिविशिष्ट व्यक्ति का बचाव कर रही है। उन्होंने कहा कि, अपराधी की जाति नहीं अपराध देखा जाता है। यशपाल आर्य ने कहा कि, अंकिता हत्याकांड एक विभत्स अपराध है इस कांड में संलिप्त सभी अपराधियों को मौत से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। भाजपा सरकार के राज में नैनीताल में वीभत्स कृत्य हुआ,लालकुआं में मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ, किच्छा में चार साल की नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई, उत्तरकाशी में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार हुआ, बागेश्वर व थराली में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया गया, देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता संस्थान में दृष्टिविहीन छात्राओं से छेड़-छाड़ की घटना हुई, हेमा नेगी, पिंकी हत्याकांड, चम्पावत में नाबालिग से बलात्कार, मंगलौर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, श्रीनगर में युवती से बलात्कार का प्रयास हुआ, द्वाराहाट में नाबालिग दलित युवती से बलात्कार हुआ, देहरादून में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया, बहादराबाद में 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या जैसे अनगिनत मानवता को शर्मशार करने वाली तथा देवभूमि की अस्मित को कलंकित करने वाली घटनायें हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन अधिकांश घटनाओं में भाजपा नेता संलिप्त पाए गए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, अंकिता का मामला राजनीति से ऊपर इंसानियत का प्रश्न है। अब कही प्रश्न उठे हैं इसलिए सरकार को ऐसे संवेदनशील मामले को एक बार और खोलकर इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने के आदेश देने चाहिए।

देवभूमि रजत उत्सवः 25 साल का सफर बेमिसाल, निरंतर प्रगति पथ पर उत्तराखंड

रजत उत्सव संग सुरक्षित शीतकालीन यात्रा का संकल्प

उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय 'देवभूमि रजत उत्सव एवं शीतकालीन चारधाम यात्रा पर आधारित कार्यक्रम' के अंतिम दिन के कार्यक्रम का मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को रजत जयंती वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन सभी वीर शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया, जिनके संघर्षों के फलस्वरूप उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ। उन्होंने विशेष रूप से मातृशक्ति के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के निर्माण में महिलाओं की भूमिका विस्मरणीय रही है और आज वे ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पृथक राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले और उत्तराखंड के गांधी स्व. श्री इंद्रमणि बडोनी जी की भी जयंती है बडोनी जी को नमन करते हुए उनके संघर्षो को याद किया। देवभूमि रजत उत्सव से रजत जयंती वर्ष पर आयोजित देवभूमि रजत उत्सव एवं शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रोत्साहन कर उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संजोया जा रहा है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत आदि सेवाओं को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया से देश को विकसित भारत बनाने का अभियान को गति दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुखवा हर्षिल से शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन कर आज पूरे वर्ष पर्यटन को गति दी जा रही है। आज हमारी सरकार एक जिला एक फेस्टिवल पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्र में गति लाने हेतु इन्वेस्टर समिट आयोजित कर 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल उतारकर औद्योगिक क्षेत्र को नई गति और सफलता प्राप्त की है। राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती हेतु हाउस ऑफ हिमालयाज, हस्तशिल्प, स्वयं सहायता समूह, शिल्प और बुनाई आदि को विशेष पहचान दी जा रही है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने हेतु होमस्टे, लखपति दीदी, वेडिंग डेस्टिनेशन आदि कार्यों को गति देकर उत्तरकाशी जनपद में ही आज 12 हजार से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के प्रयास से ही आज उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में लगभग 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आज उत्तराखंड राज्य युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी देश में अग्रणी है अभी तक हमारी सरकार ने 26 हजार 500 से अधिक युवाओं को योग्यता एवं पारदर्शिता के साथ नौकरी दी है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत् विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के साथ अस्तित्व में आए झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों की तुलना में आज हम कुछ क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने हेतु 23 करोड़ की लागत से उत्तरकाशी में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है। 46 करोड़ की राशि से पुरोला में उपजिला अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिल्क्यारा टनल का कार्य भी अंतिम चरण में है जिससे यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी कम होकर आम नागरिकों को सहूलियत के साथ पर्यटन को एक नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकना तो असंभव है परन्तु अपनी तैयारियों को बेहतर कर उनके नुकसान को कम कर सकते है जिसके लिए अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों की निगरानी हेतु निगरानी सिस्टम लगाने पर कार्य हो रहा है। धराली आपदा पीड़ितों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनके लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून, धर्मांतरण कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद आदि कानूनों को लागू कर सरकारी भूमि पर अवैध कबजे वाली भूमि को मुक्त कराया है और कहा कि देवभूमि की संस्कृति के साथ किसी को भी छेड़-छाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। यूसीसी को लागू कर सभी के लिए एक समान कानून की व्यवस्था की है।

गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे कर आज हमारा राज्य

शीतकालीन चारधाम यात्रा पर आधारित रजत जयंती वर्ष मना रहा है। उत्तराखंड निर्माण का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साकार किया था। जिसे आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु शीतकालीन यात्रा का प्रोत्साहन कर नई गति दी जा रही है।

आज कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता व स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही चित्रकला, रंगोली, नृत्य और निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। देवभूमि रजत उत्सव पर लगाई गई विकास प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनकर उभरी, जिसमें राज्य के पिछले 25 वर्षों के विकास सफर को चित्रों और वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया है। ये डिजिटल प्रदर्शनियों ने लोगो को खूब अपनी और आकर्षित कर रही है। डिजिटल प्रदर्शनी में आधुनिक तकनीक, इंटरएक्टिव गेम्स एवं डिजिटल माध्यमों के जरिए उत्तराखण्ड की विकास यात्रा को प्रदर्शित जा रहा है।

सायंकाल में आज देवभूमि रजत उत्सव समारोह में संगीता ढौंडियाल व पांडावाज बैंड की मनमोहक प्रस्तुति प्रस्तुत की जाएगी। बीते दो दिनों में अजय भारती समूह, अज्जू तोमर व श्वेता महारा की रंगारंग प्रस्तुतियों ने लोगो को झूमने पर मजबूर कर दिया है।

कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भाजपा नागेन्द्र चौहान,दर्जाधारी राज्य मंत्री राम सुंदर नौटियाल, प्रताप सिंह पंवार, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. स्वराज विद्वान, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, केदार सिंह रावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, ब्लॉक प्रमुख ममता पंवार, गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट, जिला महामंत्री महावीर सिंह नेगी, प्रशुराम जगुड़ी, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल, अपर निदेशक सूचना आशीष कुमार त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एसआईआर के लिए उत्तराखंड में 167 नए एईआरओ तैनात

वर्तमान में 70 ERO और 268 AERO सम्पादित कर रहे निर्वाचन सम्बंधी कार्य

डॉ. विजय कुमार जोगदंडे,
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

167 नए एईआरओ के बाद कुल अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कराएंगे एसआईआर सम्पन्न

उत्तराखण्ड में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियों को लेकर 167 नए अफसरों की तैनाती की गई है। प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर के मध्यनजर 167 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) की नियुक्ति की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में 70 विधानसभा क्षेत्रों में एसडीएम स्तर के 70 ईआरओ और तहसीलदार स्तर के 268 एईआरओ तैनात हैं। इसके अतरिक्त 167 नए एईआरओ की नियुक्ति के बाद प्रदेश में 435 एईआरओ आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण और इसकी तैयारियों को सम्पादित करेंगे।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि आयोग द्वारा नियुक्त 167 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सिर्फ आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें मुख्य रुप से खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, चकबन्दी अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

जिलेवार तैनात नए एइआरओ
उत्तरकाशी- 11
चमोली- 20
रुद्रप्रयाग- 08
टिहरी गढ़वाल- 12
देहरादून- 13
हरिद्वार- 19
पौड़ी गढ़वाल- 20
पिथौरागढ़- 14
बोगश्वर- 13
अल्मोड़ा- 12
चम्पावत- 06
नैनीताल- 11
ऊधमसिंह नगर- 18

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर "बीएलओ आउटरीच अभियान" के तहत मतदाताओं से संपर्क, समन्वय और संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ईआरओ और एईआरओ इस अभियान में बीएलओ द्वारा किए जा रहे आउटरीच अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

वीरेंद्र सहवाग ने डीडीए डायरेक्टर को सम्मानित किया

संदीप गुप्ता को 'भारत में सर्वश्रेष्ठ डिफेंस मेंटर' का खिताब मिला

दून डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर, सबमरीनर संदीप गुप्ता (रिटायर्ड) को 14 दिसंबर को दिल्ली में हुए प्रतिष्ठित ग्लोबिले लीडरशिप अवॉर्ड्स 2025 समारोह में 'भारत में सर्वश्रेष्ठ डिफेंस मेंटर' का खिताब दिया गया।

यह बड़ा सम्मान, जो डिफेंस में जाने की इच्छा रखने वालों को तैयार करने में संदीप गुप्ता के बेजोड़ समर्पण को पहचानता है, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और आइकन वीरेंद्र सहवाग ने प्रदान किया। इस पल ने भविष्य की लीडरशिप में डीडीए के योगदान के राष्ट्रीय महत्व को उजागर किया।

इस मौके पर संदीप गुप्ता के साथ मंच पर उनके बेटे, त्रिशक्ति यूथ हब के सीईओ, एकलव्य गुप्ता भी मौजूद थे, जो उस मजबूत पिता-पुत्र की साझेदारी का प्रतीक है जो इस संस्थान की सफलता को आगे बढ़ा रही है। यह पुरस्कार इस बात का पक्का सबूत है कि गुप्ता परिवार का विजन पूरे देश में डिफेंस मेंटरशिप के लिए एक सुनहरा स्टैंडर्ड तय कर रहा है।

गणित केवल संख्याओं और सूत्रों तक सीमित विषय नहीं है: डॉ. राणा

देव भूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय, देहरादून के प्रांगण में राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर एक गरिमामय एवं बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य गणित के महत्व को समाज तथा शिक्षा के क्षेत्र में रेखांकित करना है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री प्रोफेसर (डॉ) जगमोहन राणा, पूर्व निदेशक जैवप्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड सरकार तथा पूर्व अध्यक्ष, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए गणित और जीवन के परस्पर समन्वय पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गणित केवल संख्याओं और सूत्रों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन, निर्णय प्रक्रिया, विज्ञान, तकनीक और प्रबंधन का आधार है। गणितीय सोच से व्यक्ति में तर्कशक्ति, विश्लेषण क्षमता और समस्या-समाधान की दक्षता विकसित होती है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होती है। प्रोफेसर राणा ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में गणित का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, अर्थशास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। अतः विद्यार्थियों को गणित को बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त उपकरण के रूप में अपनाना चाहिए। इस अवसर पर प्रोफेसर (डॉ.) अनीता रावत, पूर्व निदेशक, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, उत्तराखंड सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अजय कुमार, प्रति-कुलपति डॉ संदीप शर्मा एवं डॉ. रितिका मेहरा, कुलसचिव डॉ. शुभाशीष तथा डीन स्टूडेंट वेल्फेयर दिग्विजय सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने राष्ट्रीय गणित दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए गणित शिक्षा को सशक्त बनाने पर बल दिया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। यह आयोजन विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ तथा गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक रहा।

विंटर कार्निवाल नैनीताल: भव्यता के बीच फिसलती व्यवस्थाएँ

नैनीताल से शीतल तिवारी

सरोवर नगरी नैनीताल में वर्ष 2018 के बाद 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित किया गया विंटर कार्निवाल केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह प्रशासनिक क्षमता, जनभागीदारी और पर्यटन प्रबंधन की भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी। पूर्व में शरदोत्सव के नाम से पहचाने जाने वाले इस आयोजन की वापसी को लेकर स्थानीय नागरिकों में उत्साह स्वाभाविक था। मैदानी इलाकों में बढ़ते प्रदूषण और कोहरे के बीच नैनीताल का मौसम पर्यटकों के लिए राहत का कारण बना और बच्चों की छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में सैलानी नगर पहुंचे। ऐसे में यह आयोजन नगर की अर्थव्यवस्था और छवि दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकता था।

आयोजन को भव्य बनाने के लिए बॉलीवुड के चर्चित कलाकार परमिश वर्मा, बी प्राक और पवन राजन को आमंत्रित किया गया, वहीं उत्तराखंड की लोकसंस्कृति को मंच देने के उद्देश्य से फौजी ललित मोहन जोशी, गोविंद दिगारी, इंदर आर्या और हिमनाथ बैंड जैसे स्थापित कलाकारों की प्रस्तुतियां भी प्रस्तावित थीं। माल रोड से मुख्य मंच तक निकाली गई कार्निवल झांकी ने आयोजन को दृश्यात्मक भव्यता प्रदान की। कागजों और योजनाओं में यह आयोजन हर दृष्टि से आकर्षक दिखाई देता था, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर उतनी संतुलित नहीं दिखी।

23 दिसंबर को जैसे ही परमिश वर्मा की प्रस्तुति शुरू हुई, दर्शकों का उत्साह अव्यवस्थित भीड़ में बदल गया। बैरिकेडिंग टूटना और दर्शकों का वीआईपी क्षेत्र तक पहुंच जाना यह संकेत देता है कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को या तो कम आंका गया या फिर उसे गंभीरता से लागू नहीं किया गया। परिणामस्वरूप कमिश्नर, जिलाधिकारी सहित कई विशिष्ट अतिथियों को कार्यक्रम स्थल छोड़ना पड़ा और कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ा। यह स्थिति किसी भी बड़े सार्वजनिक आयोजन के लिए चेतावनी मानी जानी चाहिए थी।

सबसे अधिक असंतोष वीआईपी व्यवस्था को लेकर सामने आया। विंटर कार्निवाल जैसे जनोत्सव में वीआईपी संस्कृति का इतना हावी हो जाना यह सवाल खड़ा करता है कि आयोजन की प्राथमिकता क्या थी–जनता या प्रोटोकॉल। बड़ी संख्या में वीआईपी पास जारी किए जाने के कारण नगर के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पूर्व पालिका अध्यक्ष, पद्मश्री सम्मानित नागरिक और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपने ही शहर के आयोजन में उपेक्षित महसूस करते दिखाई दिए। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नगर पालिका अध्यक्ष चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पद की गरिमा के कारण उसे शहर का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, और उस पद की अनदेखी वास्तव में पूरे नगर की लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनदेखी मानी जाती है। स्थानीय कलाकारों में भी यह भावना गहराई कि जिनके कंधों पर वर्षों से नैनीताल की सांस्कृतिक पहचान टिकी रही, उन्हें अपने ही शहर में आयोजित बड़े मंच पर अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। यह स्थिति तब और विडंबनापूर्ण हो जाती है जब वही कलाकार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हों। इससे यह संदेश गया कि आयोजन की चमक-दमक में स्थानीय पहचान कहीं पीछे छूट गई।

मीडिया और प्रशासन के बीच उत्पन्न तनाव ने आयोजन की व्यवस्थागत कमजोरियों को और उजागर किया। चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका केवल समाचार प्रसारण तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे सार्वजनिक आयोजनों की पारदर्शिता का भी प्रतीक होते हैं। अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन से पूर्व पत्रकारों का धरना यह दर्शाता है कि संवाद और सम्मान का अभाव किसी भी सफल आयोजन को असहज बना सकता है। हालांकि सभी पक्षों ने नगर की गरिमा और परंपरा को ध्यान में रखते हुए संयम दिखाया, जो नैनीताल की सामाजिक समझदारी को दर्शाता है।

इन सबके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद नैनीताल को लगभग 121 करोड़ 52 लाख 46 हजार रुपये की लागत से 13 विकास कार्यों की सौगात देना इस आयोजन का सबसे ठोस और सकारात्मक पक्ष रहा। यह निर्णय दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे आयोजन की उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। फिर भी, समापन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता और उसमें उठाए गए सवाल यह संकेत देते हैं कि आयोजन समिति और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय की कमी रही। उन्होंने आमंत्रण व्यवस्था, प्रोटोकॉल और कार्यक्रम संचालन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और यह स्पष्ट किया कि नगर से निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका और सम्मान को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। आम जनता के बीच यह चर्चा भी मुखर रही कि यदि आयोजन वास्तव में जनसहभागिता के लिए था, तो उसे वीआईपी सीमाओं में क्यों बांधा गया।

कुल मिलाकर, इस विंटर कार्निवाल को असफल कहना न तो उचित होगा और न ही न्यायसंगत। जिस स्तर की भव्यता और बड़े कलाकारों की मौजूदगी के साथ यह आयोजन किया गया था, यदि व्यवस्थागत कमियां सामने न आतीं, तो यह कार्यक्रम नैनीताल के सबसे भव्य और यादगार आयोजनों में शामिल हो सकता था। असली कसौटी यह होती है कि जनता, स्थानीय प्रतिनिधि और स्थानीय संस्कृति उसमें कितनी सम्मानित महसूस करती है। यदि भविष्य में इस अनुभव से सीख लेते हुए आयोजन के समय, स्वरूप और प्रबंधन पर पुनर्विचार किया गया–जैसे शरदोत्सव को सितंबर-अक्टूबर के अनुकूल मौसम में आयोजित करना–तो ऐसे उत्सव वास्तव में नैनीताल की पहचान और पर्यटन को नई ऊंचाई दे सकते हैं।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

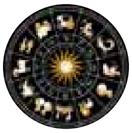
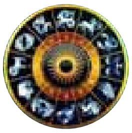
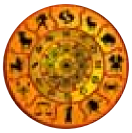

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि– घर की किसी समस्या का समाधान वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन से मिल जाएगा, जिससे आप तनावमुक्त होकर अपने व्यक्तिगत कामों पर ध्यान दे पाएंगे। आर्थिक पक्ष को लेकर भूमि संबंधी कार्यों में अभी बहुत बड़े लाभ की उम्मीद न रखें और परिस्थितियों से समझौता करना ही बेहतर रहेगा। भाग्यशाली रंग– सफेद, भाग्यशाली अंक– 1

वृषभ राशि– कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति जरूरी है, अपनी देखरेख में काम करे, आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। व्यापारिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता से लाभ बढ़ेगा। पति-पत्नी के बीच आपसी प्रेम और तालमेल बना रहेगा। भाग्यशाली रंग– बादामी, भाग्यशाली अंक– 5

मिथुन राशि– घर में रिश्तेदारों के आने से मेलजोल का माहौल रहेगा, सभी लोग आपसी मुलाकात का आनंद उठाएंगे। परिवार के सदस्यों पर बहुत अधिक अनुशासन न थोपें, इससे वे परेशान हो सकते हैं। व्यावसायिक व्यवस्था बेहतर रहेगी, लेकिन फाइनेंस और पैसों से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भाग्यशाली रंग– आसमानी, भाग्यशाली अंक– 7

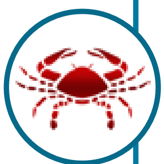

कर्क राशि– परिवार की हर छोटी-बड़ी जरूरत को पूरा करने में आपको मानसिक शांति और आनंद मिलेगा। योजनाओं को लागू करने में ज्यादा सोच-विचार न करें, वरना मौका हाथ से निकल सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना नुकसानदेह हो सकता है। परिवार में व्यवस्थित और सुखद माहौल रहेगा। भाग्यशाली रंग– नीला, भाग्यशाली अंक– 8

सिंह राशि– पब्लिक रिलेशन और नेटवर्किंग से आपको व्यवसाय के नए स्रोत हासिल होंगे। कोई भी गोपनीय बात अपरिचित लोगों के बीच उजागर न करें। अगर आज कोई यात्रा का प्रोग्राम है, तो उसे स्थगित रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में अभी थोड़ी मंदी रह सकती है। घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। भाग्यशाली रंग– आरेंज, भाग्यशाली अंक– 4

कन्या राशि– ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, अपनी योजनाओं को गोपनीय तरीके से आगे बढ़ाएं, सफलता निश्चित है। किसी घनिष्ठ मित्र का सहयोग आपके कार्यों में सहायक रहेगा। थोड़ी सी सतर्कता रखने से आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। व्यवसाय में आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। संबंधी नियमों का पूर्ण पालन करें। भाग्यशाली रंग– नीला, भाग्यशाली अंक– 6

तुला राशि– धार्मिक संस्थाओं के कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा करना आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। युवा वर्ग विशेष रूप से सावधान रहें। ऑफिस में दूसरों की बातों में न आकर अपने काम पर ध्यान दें। परिवार और जीवनसाथी का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा। भाग्यशाली रंग– बादामी, भाग्यशाली अंक– 2

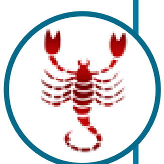

वृश्चिक राशि– पारिवारिक और व्यक्तिगत फैसले स्वयं ही लें, दूसरों का हस्तक्षेप घर की व्यवस्था में तनाव पैदा कर सकता है। आय सामान्य रहेगी, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर काबू रखने की जरूरत है। व्यावसायिक व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे पर विश्वास बनाए रखना आवश्यक हैं। भाग्यशाली रंग– केसरिया, भाग्यशाली अंक– 6

धनु राशि– सामाजिक गतिविधियों में समय बिताने से आपकी साख बढ़ेगी। धैर्य से काम लें। व्यापार में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर लें। मनोरंजन या घूमने-फिरने का प्रोग्राम बनेगा। प्रेमियों के लिए आज डेटिंग का अवसर है। व्यायाम और योग करना आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। भाग्यशाली रंग– हरा, भाग्यशाली अंक– 3

मकर राशि– भविष्य की योजनाएं बनाते समय दूसरों के प्रभाव में आने के बजाय अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें, यह आपकी जिम्मेदारी है। समय के प्रबंधन पर ध्यान दें। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसे सुलझाएं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। भाग्यशाली रंग– गुलाबी, भाग्यशाली अंक– 7

कुंभ राशि– अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का हल मिलेगा। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें। व्यवसाय के लिए समय अभी बहुत अनुकूल नहीं है। सरकारी कर्मचारियों पर आज भी काम का बोझ अधिक रहेगा। भाग्यशाली रंग– लाल, भाग्यशाली अंक– 3

मीन राशि– काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तल्खी आ सकती है। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेद होने की स्थिति बन रही है, इसे धैर्य से सुलझाएं। अपनी महत्वपूर्ण फाइलों और दस्तावेजों को बहुत संभालकर रखें। अस्त-व्यस्त दिनचर्या से पेट खराब हो सकता है। भाग्यशाली रंग– नीला, भाग्यशाली अंक– 8

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027